



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938

No. 569]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुराज्य सहकारी समितियाँ नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को बहुराज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाये।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बहुराज्य सहकारी समितियाँ नियम, 2002 में नियम 3 में उपनियम (1) में

i. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

” (ख) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई रकम के साथ और मुख्य संप्रवर्तक द्वारा सम्यकतः प्रमाणित उनके पहचान पते सबूतों सहित उनके द्वारा संदर्भ प्रवेश फीस”

ii. खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :

”(च) प्रत्यय से संबंधित उद्देश्यों और कृत्यों या वह प्रयोजनीय उद्देश्यों वाली प्राथमिक वह राज्य सहकारी सोसाइटी प्रचालन के क्षेत्र में आरंभिक रूप से दो राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(छ) प्रत्यय से संबंधित उद्देश्यों और कार्यों या बहुप्रयोजनीय उद्देश्यों वाली समितियों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, अर्थात् :-

(i) संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां समिति के प्रचालन का प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र हो।

(ii) मुख्य संप्रवर्तक और संप्रवर्तक की पृष्ठभूमि और अन्य प्रत्यय पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जो राज्य के रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा सम्यकतः प्रमाणित हो जहां सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अब स्थित होना प्रस्तावित है।

(ज) अधिनियम की धारा 3 के खंड (द) में परिभाषित “राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी” के अलावा समिति को अपने नाम में “नेशनल, इंडियन, भारतीय, राष्ट्रीय” या समतुल्य शब्दों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी और सोसाइटी का नाम “संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों का उल्लंधन नहीं करेगा।

(3) उक्त नियमों में नियम 8 के उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :

“ (4) केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से एक बहु राज्य सहकारी समिति, जो सहकारी बैंक न हो, सोसाइटी के समुचित कृत्य के अध्यधीन, भारत में किसी भी स्थान पर शाखाएं और कारोबार के स्थान खोल सकेगी।

[फा. सं. एल-11012/2/2003-एलएंडएम]

आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. संख्या 790(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात उनमें सा.का.नि. 717(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 के और सा.का.नि. 447(अ) तारीख 15 जून, 2012 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2016

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by section 124 of the Multi State Co-operative Societies Act 2002(39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2016.
 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 3, in sub-rule (1),
- (i) for clause (b), the following clause shall be substituted namely ;
- “(b) the list of persons who have contributed to the share capital, together with the amount contributed by each of them and the admission fee paid by them along with their ID-address proofs duly attested by the Chief Promoter ;”;
- (ii) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely ;
- “(f) primary multi state co-operative societies having objects and functions relating to credit or having multi-purpose objects shall be registered initially with two States or the Union Territories as area of operation ;
- (g) societies having objects and functions relating to credit or having multi-purpose objects

shall be required to submit the following documents, namely :-

- (i) no objection Certificate from the Registrar of Cooperative Societies of the states or the union territories concerned where the proposed area of operation of the society extends;
- (ii) verification certificate of the background and other credentials of the Chief Promoter and Promoters duly certified by the Registrar of Cooperative Societies of the State where the Registered Office of the Society is proposed to be located;
- (h) societies other than ‘National Cooperative Societies’ as defined in clause(r) of section 3 of the Act shall not be permitted to use the words “National, Indian, Bhartiye, Rashtriye” or equivalent in their names and the name of the society shall not violate the provisions of the “Emblems And Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950(12 of 1950).”

(3) In the said rules, in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(4) A multi State co-operative society, not being a co-operative bank, may open branches or places of business in any place in India with the prior approval of the Central Registrar and the same shall be granted, subject to proper functioning of the society.”.

[F. No. L-11012/2/2003-L&M]

ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 790 (E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 717(E), dated the 12th November, 2007 and G.S.R. 447(E), dated the 15th June, 2012.